[2012] 7 एस.सी.आर. 1139

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम

बनाम

अध्यक्ष, राजस्थान रोडवेज यूनियन एवं अन्य

(2012 की सिविल अपील संख्या 6639)

सितम्बर 18, 2012

[न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन एवं न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा]

कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971:

पेंशन योजना– कर्मचारी योजना के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग नहीं कर रहा है– निर्धारित किया: क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा जारी दिनांक 9.4.1971 की अधिसूचना नियोक्ता द्वारा प्रसारित की गई थी– निगम पत्र दिनांक 30.7.1971– परिणामस्वरूप, कई कर्मचारियों ने योजना का विकल्प चुना और उनमें से कुछ, जिनमें मृतक भी शामिल थे, ने इसका विकल्प नहीं चुना– यह मानने का कोई कारण नहीं है कि कर्मचारी योजना और अधिसूचनाओं से अनभिज्ञ थे– इसके अलावा, मृतक की पत्नी को भविष्य निधि की पूरी राशि प्राप्त हुई थी– नौ साल बाद कर्मचारी संघ द्वारा उठाया गया विवाद बिल्कुल निराधार है– कर्मचारी भविष्य निधि और पारिवारिक पेंशन योजना, 1952– श्रम कानून।

अपीलार्थी–निगम में 1962 में भर्ती हुए एक कर्मचारी की सेवा के दौरान 1982 में मृत्यु हो गई। उन्होंने कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 के तहत विकल्प का प्रयोग नहीं किया था और इसलिए, उनकी पत्नी ने अंशदायी भविष्य निधि स्वीकार कर ली और पारिवारिक पेंशन के लिए कोई दावा नहीं किया। हालाँकि, नौ साल बाद, प्रतिवादी–संघ ने पारिवारिक पेंशन के लिए मृतक–कर्मचारी की पत्नी का दावा उठाया और अंततः औद्योगिक अधिकरण ने इसे यह कहते हुए अनुमति दे दी कि कर्मचारी को योजना के तहत विकल्प का प्रयोग करने के उसके अधिकार के बारे में सूचित नहीं किया गया था। एकल न्यायाधीश के समक्ष निगम की रिट याचिका और उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष उसकी अपील असफल रही।

निगम द्वारा दायर तत्काल अपील में, न्यायालय के समक्ष विचार हेतु प्रश्न था: क्या मृत कर्मचारी की पत्नी कर्मचारी द्वारा योजना के तहत अपने विकल्प का प्रयोग करने में विफलता पर कर्मचारी पारिवारिक पेंशन योजना 1971 के तहत पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार थी, खासकर तब जब दावेदार को नियोक्ता द्वारा रखे गए फंड से पूरी भविष्य निधि राशि पहले ही मिल चुकी हो।

अपील स्वीकार करते हुए अदालत ने यह निर्धारित किया:

1.1 अपीलकर्ता निगम द्वारा जारी पत्र दिनांक 30.7.1971 के साथ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 9.4.1971 को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त और अपीलकर्ता निगम ने सभी विभागों/यूनियनों के साथ–साथ निगम के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को सूचित किया था कि यदि वे पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो वे अपने आवश्यक विकल्प का उपयोग करें। तथ्य यह दर्शाते हैं कि उस समय कई कर्मचारियों ने विकल्प चुना था और उनमें से कुछ ने इसका विकल्प नहीं चुना था, क्योंकि वे सीपीएफ योजना के तहत भविष्य निधि प्राप्त करने में रुचि रखते थे, न कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद योजना के तहत पारिवारिक पेंशन पाने में। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि कर्मचारी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के साथ–साथ निगम द्वारा जारी

अधिसूचना से अनभिज्ञ थे। तथ्य यह भी दर्शाते हैं कि मृत कर्मचारी की पत्नी को पहले ही पूरी भविष्य निधि राशि मिल चुकी है क्योंकि कर्मचारी ने योजना के तहत विकल्प नहीं चुना था। हालाँकि, नौ साल बाद, प्रतिवादी संघ एक विवाद उठा रहा है जो बिल्कुल असमर्थनीय है।

1.2 **अधिकरण के साथ–साथ एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने मामले के तथ्यों को ठीक से न समझने में गंभीर त्रुटि की है और एक विकृत निष्कर्ष दिया है जो आवश्यक रूप से हस्तक्षेप की मांग करता है। तदनुसार, अधिकरण के फैसले के साथ–साथ एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसलों को रद्द किया जाता है।**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 6639/2012

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर के डिवीजन बेंच सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 960/2011 में एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 2099/1999 के निर्णय और आदेश दिनांक 29.06.2011 से।

अपीलकर्ता की ओर से एस के भट्टाचार्य।

प्रतिवादियों की ओर से बी रमण मूर्ति।

न्यायालय का फैसला न्यायमूर्ति के. एस. राधाकृष्णन द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति प्रदान।

2. इस मामले में, हम इस सवाल से चिंतित हैं कि क्या किसी कर्मचारी की विधवा योजना के तहत अपने विकल्प का उपयोग करने में नियोक्ता की विफलता पर कर्मचारी पारिवारिक पेंशन योजना, 1971 (संक्षेप में 'योजना') के तहत पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार है, खासकर तब जब दावेदार को निगम द्वारा बनाए गए फंड से पूरी भविष्य निधि राशि पहले ही मिल चुकी हो।

3. प्रतिवादी संघ ने स्वर्गीय हरि सिंह की विधवा की ओर से राज्य सरकार के समक्ष योजना के तहत पारिवारिक पेंशन के लिए दावा किया। राज्य सरकार ने दावे के निर्णय के लिए मामले को श्रम एवं औद्योगिक अधिकरण, जयपुर (संक्षेप में 'अधिकरण') के पास भेज दिया। अधिकरण ने योजना की जांच करने के बाद यह विचार किया कि कर्मचारी को योजना के तहत विकल्प का प्रयोग करने के अपने अधिकार के बारे में सूचित नहीं किया गया था, परिणामस्वरूप, आवेदन की अनुमति दी और अपीलकर्ता निगम को हरि सिंह जो निगम की सेवा में ड्राइवर के रूप में कार्यरत थे, की विधवा को पारिवारिक पेंशन वितरित करने का निर्देश दिया।

4. अपीलकर्ता–निगम ने 1999 की एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2099 दायर करके राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के समक्ष मामला उठाया, जिसे विद्वान_एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया और, बाद में, डी.बी. सिविल स्पेशल अपील (रिट) नंबर 960/2011 में अपने फैसले दिनांक 29.6.2011 द्वारा डिवीजन बेंच द्वारा भी पुष्टि की गई। उसी से व्यथित होकर, अपीलकर्ता–निगम द्वारा अपील प्रस्तुत करी गई है।

5. अपीलकर्ता–निगम की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री एस.के. भट्टाचार्य ने प्रस्तुत किया कि अधिकरण के साथ–साथ निचली अदालतों ने भी योजना के प्रावधानों को गलत समझा है और पारिवारिक पेंशन के लिए उठाए गए दावे के निर्णय के लिए सभी प्रासंगिक और भौतिक तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि तथ्यों को पूरी तरह से गलत तरीके से पढ़ा गया, जिसके कारण गलत तर्क सामने आए, जिसके परिणामस्वरूप तथ्यों के साथ–साथ कानून पर भी गलत निर्णय दिया गया।

6. प्रतिवादी संघ की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री बी. रमण मूर्ति ने प्रस्तुत किया कि यह न्यायालय नीचे के सभी प्राधिकारियों द्वारा दिए गए समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और इस न्यायालय द्वारा निर्धारण के लिए कानून का कोई प्रश्न नहीं उठाया गया है।

7. पक्षों द्वारा उठाए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों की जांच करने के लिए, मामले के तथ्यों को समझना आवश्यक है ताकि यह न्यायालय यह जांच कर सके कि क्या अधिकरण के साथ–साथ नीचे के न्यायालयों ने भी विकृत निष्कर्ष दिया है, जिस पर एक उचित व्यक्ति किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत नहीं पहुंच पाता।

8. कर्मचारी हीरा सिंह को 22.3.1962 को अपीलकर्ता–निगम की सेवा में ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया था, और बाद में, उन्हें सहायक यातायात निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। वर्ष 1971 में, केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि और पारिवारिक पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (संक्षेप में 'पी.एफ. अधिनियम') में उपयुक्त संशोधन करके पारिवारिक पेंशन से संबंधित एक योजना शुरू की। योजना का लाभ उठाने के इच्छुक कर्मचारियों को योजना के तहत अपने विकल्प का उपयोग करना था और उक्त उद्देश्य के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 1.9.1971 थी। अपीलकर्ता निगम के अनुसार, हरि सिंह ने योजना के तहत उस विकल्प का प्रयोग नहीं किया और सेवा में रहते हुए 30.5.1982 को उनकी मृत्यु हो गई। अंशदायी भविष्य निधि, नियमों के अनुसार, कर्मचारी की विधवा को वितरित की गई और उसे प्राप्त भी किया गया। पारिवारिक पेंशन के लिए कोई दावा नहीं किया गया क्योंकि कर्मचारी ने योजना का लाभ नहीं चुना था।

9. हालाँकि, प्रतिवादी संघ ने नौ साल बाद राज्य सरकार के समक्ष एक याचिका दायर करके विधवा के दावे को उठाया, जिसका हम पहले ही संकेत दे चुके हैं, अधिकरण को भेजा गया था और प्रतिवादी संघ के पक्ष में निर्णय लिया गया था।

10. इस मामले में, हम इस सवाल से चिंतित हैं कि क्या हरि सिंह ने उस योजना का लाभ चुना था जो वर्ष 1971 में लागू हुई थी और क्या अपीलकर्ता–निगम की ओर से कर्मचारियों को ऐसी योजना के अस्तित्व और पारिवारिक पेंशन के लिए विकल्प चुनने के उनके अधिकार के बारे में तुरंत सूचित करने में विफलता हुई थी।

11. तथ्यों के आधार पर हम पाते हैं कि निगम ने 30.7.1971 को एक अधिसूचना जारी कर कर्मचारियों से आवश्यक विकल्प मांगा था। उस अधिसूचना के अनुसरण में, कई कर्मचारियों ने योजना के लिए अपने विकल्प का प्रयोग किया था और कुछ ने उसे नहीं चुना, क्योंकि वे केंद्रीय भविष्य निधि योजना (संक्षेप में 'सीपीएफ योजना') के तहत भविष्य निधि प्राप्त करने के इच्छुक थे। हरि सिंह ने कई अन्य कर्मचारियों की तरह इस योजना का विकल्प नहीं चुना, क्योंकि वह योजना के तहत पारिवारिक पेंशन के बजाय सीपीएफ योजना के तहत भविष्य निधि प्राप्त करने के इच्छुक थे।

12. अपीलकर्ता–निगम ने 9.4.1971 को उनके द्वारा जारी अधिसूचना को अनुबंध पी/1 के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसका प्रवर्ती भाग इस प्रकार है:

"मैं आपकी जानकारी के लिए और कर्मचारी भविष्य निधि के सभी सदस्यों को पारिवारिक पेंशन–सह–जीवन बीमा योजना के प्रावधानों को समझाने के लिए कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन योजना, 1971 की एक प्रति भेज रहा हूं जो 1 मार्च, 1971 से लागू हुई है।

2. इस योजना के पैरा 4 के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी, जो 28.2.1971 को कर्मचारी भविष्य निधि का या अधिनियम की धारा 17 के तहत छूट प्राप्त कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों के भविष्य निधि का सदस्य है, को फॉर्म । (प्रतियां संलग्न) में 1 मार्च 1971 से तीन महीने की अवधि के अंदर अपने विकल्प का उपयोग करना होगा, और निर्दिष्ट समय के तुरंत बाद इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा ।

3. जो कर्मचारी 1 मार्च, 1971 के बाद पारिवारिक पेंशन निधि का सदस्य बनने का विकल्प चुनते हैं या इसके हकदार हैं, उनसे फॉर्म 2 (प्रतियां संलग्न) में अपने और अपने परिवार से संबंधित विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा और जहां भी आवश्यक हो, इसे (विकल्प फॉर्म नंबर 1 के साथ में) भेजा जा सकता है।

4. कृपया विकल्प प्रपत्र और नामांकन प्रपत्र निम्नलिखित विवरण के साथ विधिवत भेजें:–

28.2.1971 को सदस्यों (ग्राहकों) की संख्या	पारिवारिक पेंशन योजना को चुनने वाले सदस्यों की संख्या	मौजूदा पीएफ लाभ जारी रखने का विकल्प चुनने वाले सदस्यों की संख्या

5. फॉर्म नंबर 1 और 2 की आगे की आवश्यकता या तो सीधे इस कार्यालय से या जयपुर, जोधपुर और अजमेर में भविष्य निधि निरीक्षकों से प्राप्त की जा सकती है।

6. अन्य जानकारी और रिटर्न जमा करने के संबंध में निर्देश निम्नानुसार होंगे:"

13. हमने देखा कि उपरोक्त अधिसूचना अपीलकर्ता निगम के सभी कर्मचारियों को जानकारी के लिए इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि वे योजना का व्यापक प्रचार करें और अधिसूचना क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय से जारी की गई थी। उपरोक्त अधिसूचना के बाद, निगम ने क्षेत्रीय प्रबंधक/प्रशासनिक अधिकारी/डिपो प्रबंधक/सहायक डिपो प्रबंधक, आरएसआरटीसी और सभी कार्यालयों को दिनांक 30.7.1971 को एक पत्र भेजकर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा जारी अधिसूचना के बारे में सूचित किया, जिसमें इस प्रकार बताया गया है:

"राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के सभी कर्मचारी जो भविष्य निधि में योगदान दे रहे हैं वे पारिवारिक पेंशन योजना 1971 के सदस्य बनने के पात्र हैं और नियोक्ता की ओर से यह अनिवार्य है कि पैरा 1 की उप–धारा (i) में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग प्रत्येक सदस्य द्वारा किया जाए, जिसे 31 अगस्त, 1971 से पहले इस योजना का सदस्य बनने का विकल्प दिया गया है। इसलिए, मैं कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 की एक प्रति घोषणा प्रपत्रों और विकल्प प्रपत्रों के साथ भेज रहा हूं, जिन्हें भविष्य निधि के प्रत्येक ग्राहक को समझाया जाना आवश्यक है और 1 मार्च, 1971 को भविष्य निधि में योगदान करने वाले प्रत्येक कर्मचारी से इस पर हस्ताक्षर करवाएं।
योजना के खंड 4(3) के तहत यह देखना आपका कर्तव्य होगा कि चुने गए प्रत्येक ग्राहक का विकल्प निम्नलिखित प्रोफार्मा में विकल्प चुनने वालों की एक सूची भी तैयार की जा सकती है और इसे ग्राहक द्वारा विशेष संदेशवाहक के माध्यम से निष्पादित घोषणा प्रपत्रों और विकल्प प्रपत्रों के साथ 31 अगस्त, 1971 तक भेजा जा सकता है।

पारिवारिक पेंशन योजना 1971 के विकल्पधारियों की सूची।

डिपो/क्षेत्र/कार्यालय का नाम....

क्रम संख्या	पिता के नाम के साथ कर्मचारी का नाम	सी.पी.एफ. खाता संख्या	डी.ए. सहित वेतन	डी.ए. सहित वेतन का 6% की दर से पी.एफ.
1	2	3	4	5
	डी.ए. सहित वेतन का पारिवारिक पेंशन राशि 11	कुल 5+ 6	वर्तमान में पी.एफ. सदस्यता में कटौती की जा रही है	टिप्पणी
	6	7	8	9

कार्यालय प्रमुख के मुहर सहित हस्ताक्षर

यह भी अनुरोध किया जाता है कि योजना को ध्यान से समझने के लिए समझाया जाए और सभी ग्राहकों को घोषणाएं और विकल्प लेते समय संबंधित लाभों के बारे में बताया जाए ताकि वे योजना में शामिल होने पर विचार कर सकें और अच्छी संख्या में इसे चुन सकें, और मैं आपसे यह भी अनुरोध करूंगा कि कृपया इस योजना का प्रचार नोटिस बोर्ड के माध्यम से भी करें।

कृपया प्राप्ति सूचना दें।"

14. जब हमने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 9.4.1971 को अपीलकर्ता निगम द्वारा जारी पत्र दिनांक 30.7.1971 के साथ पढ़ा, यह स्पष्ट है कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के साथ–साथ अपीलकर्ता–निगम ने सभी विभागों/यूनियनों के साथ–साथ निगम के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को सूचित किया था कि यदि वे पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त करना

चाहते हैं तो वे अपने आवश्यक विकल्प का उपयोग करें। तथ्य यह दर्शाते हैं कि उस समय कई कर्मचारियों ने विकल्प चुना था और उनमें से कुछ ने इसका विकल्प नहीं चुना था, क्योंकि वे सीपीएफ योजना के तहत भविष्य निधि प्राप्त करने में रुचि रखते थे, न कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद योजना के तहत पारिवारिक पेंशन पाने में। हमारे पास यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि कर्मचारी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के साथ–साथ निगम द्वारा जारी अधिसूचना से अनजान थे। तथ्यों से यह भी पता चलता है कि हरि सिंह की पत्नी को पहले ही भविष्य निधि की पूरी राशि मिल चुकी थी और चूंकि हरि सिंह ने इस योजना का विकल्प नहीं चुना था। हालाँकि, नौ साल बाद, प्रतिवादी संघ एक विवाद उठा रहा है, जो हमारे विचार में, बिल्कुल असमर्थनीय है। अधिकरण के साथ–साथ निचली अदालतों ने मामले के तथ्यों को ठीक से न समझने में गंभीर त्रुटि की है और एक विकृत निष्कर्ष दिया है जो आवश्यक रूप से हस्तक्षेप की मांग करता है।

15. तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करने और अधिकरण के फैसले के साथ–साथ उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच के फैसलों को रद्द करने के इच्छुक हैं। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

आर.पी. अपील स्वीकृत।

Akanksha Bajpai